

कार्यकारी सारांश

राजस्थान सेकेंडरी टाउन डेवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट, (RSTDSP), निवेश परियोजनाओं का चौथा चरण एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा वित्तपोषित है और राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RUDSICO) द्वारा कार्यान्वित है, जिसे पहले राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट परियोजना (आरयूआईडीपी) के नाम से जाना जाता था। आरएसटीडीएसपी लगभग 14 शहरों में पानी और अपशिष्ट जल सेवाओं में सुधार की दिशा में राजस्थान सरकार के चल रहे प्रयासों का समर्थन करेगा। RSTDSP सेक्टर, ऋण के माध्यम से 20,000-115,000 के बीच आबादी वाले माध्यमिक शहरों में जल आपूर्ति और सीवरेज (WSS) सेवाओं में सुधार करना चाहता है। परियोजना निम्नलिखित प्रभावों के साथ संरेखित है: (i) राजस्थान के सभी शहरी क्षेत्रों में पीने योग्य, सस्ती, विश्वसनीय, न्यायसंगत और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ पेयजल आपूर्ति तक पहुंच में सुधार होगा। (ii) शहरी आबादी, विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। राजस्थान के माध्यमिक शहरों में शहरी सेवा वितरण में सुधार होगा।

लाडनू टाउन सीवरेज सबप्रोजेक्ट आरएसटीडीएसपी के इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट के तहत प्रस्तावित सबप्रोजेक्ट्स में से एक है। वर्तमान में, लाडनू में कोई सीवरेज प्रणाली नहीं है और रसोई और स्नानघर से अपशिष्ट जल को नालों या जमीन पर अंत में समाप्त होने वाले तूफानी जल नालों में छोड़ दिया जाता है, जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है और भूजल को दूषित करता है। शहर में खुले में शौच कोई आम बात नहीं है। अधिकांश आवासीय, वाणिज्यिक भवनों और शैक्षणिक संस्थानों में साइट पर सेप्टिक टैंक और सोक पिट हैं। सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गंदा पानी सीधे खुले नालों में जाता है। इसलिए, शहर में प्रस्तावित सीवरेज प्रणाली से शहर की पर्यावरण और स्वच्छता की स्थिति में वृद्धि होगी और निवासियों की रहने की स्थिति में वृद्धि होगी।

संभावित प्रभावों की जांच और आकलन- एडीबी को, बैंक के संचालन के सभी पहलुओं में पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है, और पर्यावरण मूल्यांकन की आवश्यकताओं को एडीबी के सुरक्षा नीति वक्तव्य (एसपीएस), 2009 में वर्णित किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अनुसार, इस उप-परियोजना को ईआईए अध्ययन या पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। सीवरेज के लिए, उप-परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन, एडीबी रैपिड एनवायरनमेंटल असेसमेंट (आरईए) चेकलिस्ट का उपयोग करके किया गया है। पूर्व-निर्माण, निर्माण और संचालन चरणों के संबंध में संभावित नकारात्मक प्रभावों की पहचान की गई थी। यह प्रारंभिक पर्यावरण परीक्षा (आईईई) लाडनू टाउन सीवरेज उप-परियोजना के तहत प्रस्तावित बुनियादी ढांचे के घटकों को संबोधित करती है।

4. वर्गीकरण (i) प्रारंभिक विस्तृत डिजाइन, और (ii) पर्यावरण के प्रति संवेदनशील घटकों की सबसे अधिक संभावना के आधार पर लाडनू सीवरेज उप-परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मूल्यांकन किया गया है। पर्यावरण मूल्यांकन में सीवरेज कार्यों और पानी की आपूर्ति के लिए एडीबी की आरईए चेकलिस्ट (REA Checklist) और "अशमन परिदृश्य चेकलिस्ट (No Mitigation Scenario Checklist)" का उपयोग किया गया था। लाडनू सीवरेज उप-परियोजनाओं के पर्यावरणीय मूल्यांकन से कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव होने की संभावना नहीं है जो अपरिवर्तनीय, विविध या अभूतपूर्व हैं। संभावित प्रभाव, ज्यादातर साइट-विशिष्ट होते हैं और उनमें से कुछ अपरिवर्तनीय होते हैं। ज्यादातर मामलों में शमन उपायों को निर्माण स्थलों पर आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले सरल उपायों के साथ डिजाइन किया जा सकता है और जो कि सिविल कार्य ठेकेदारों को पता हो।

5. लाडनू टाउन सीवरेज उप-परियोजना को एडीबी एसपीएस 2009 के अनुसार पर्यावरण श्रेणी बी के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि कोई महत्वपूर्ण प्रभाव परिकल्पित नहीं है। तदनुसार, यह आईईई पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करती है और यह सुनिश्चित करने के लिए शमन और निगरानी उपाय (Mitigation and Monitoring Measures) प्रदान करता है कि परियोजना के परिणामस्वरूप कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

परियोजना का दायरा- उप-परियोजना को समग्र और एकीकृत तरीके से सीवरेज बुनियादी ढांचे में अंतराल को दूर करने के लिए तैयार किया गया है। आरएसटीडीएसपी का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित सीवेज संग्रह प्रदान करना है और सीवेज उपचार में चल रहे निवेश के साथ, इसका सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इस उप-परियोजना के तहत निवेश में शामिल हैं **फिकल स्लज** के सह-उपचार सहित एसबीआर प्रक्रिया पर आधारित दो एसटीपी का निर्माण- (i) श्री माधव बी.एड कॉलेज के पास 5.50 MLD क्षमता एसटीपी का निर्माण और (ii) विश्वनाथ पुरा रोड के पास 2.40 एमएलडी क्षमता का एसटीपी, ट्रीटेड एफ्लुएंट के पुनः उपयोग के लिए दोनों ट्रीटेड एफ्लुएंट एलिवेटेड रिजर्वोइयर (टीईईआर), ट्रीटेड एफ्लुएंट स्टोरेज रिजर्वोइयर (टीईएसआर) के साथ (iii) 127.10 किमी की सीवर लाइन बिछाना और 13.63 किमी लंबाई की ट्रेचलेस सीवर लाइन (iv) 11500 हाउस सर्विस कनेक्शन (v) 2 सीआरएमसी।

पर्यावरण का विवरण- उप-परियोजना घटक नागौर जिले के लाडनू शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित हैं जो कई वर्षों पहले शहरी उपयोग में परिवर्तित हो गए थे, और इन स्थलों पर कोई प्राकृतिक आवास नहीं बचा है। लाडनू की जलवायु गर्म और शुष्क होती है। गर्मी के महीनों के दौरान अधिकतम तापमान अक्सर 47°C से ऊपर शांत हो जाता है। अधिकांश आवासीय, वाणिज्यिक भवनों और शैक्षणिक संस्थानों में साइट पर सेप्टिक टैंक और सोक पिट हैं। सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गंदा पानी सीधे खुले नालों में जाता है। जो अंततः शहर की जल भंडारण प्रणाली को प्रदूषित करते हैं। परियोजना स्थल सरकारी भूमि (संरचनाओं के लिए) और मौजूदा सड़क मार्ग (आरओडब्ल्यू) में पाइप बिछाने के लिए स्थित हैं। परियोजना स्थानों में या उसके आस-पास कोई संरक्षित क्षेत्र, आर्द्रभूमि, मैंग्रोव या मुहाना नहीं हैं। मिट्टी गहरी है, और पाइप बिछाने के लिए चट्टानों को काटने की आवश्यकता नहीं है। लाडनू शहर की जलवायु गर्मियों में शुष्क और गर्म और सर्दियों में ठंडी होती है। लाडनू शहर में बारिश कम है।

संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और शमन उपाय- इस मसौदे में आईईईई, बेहतर बुनियादी ढांचे के स्थान, डिजाइन, निर्माण और संचालन के संबंध में नकारात्मक प्रभावों की पहचान की गई थी। परियोजना के डिजाइन या स्थान के कारण होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं थे क्योंकि साइट योजना और प्रारंभिक डिजाइन में विभिन्न उपाय पहले से ही शामिल हैं। लडनू के भीतर कोई पर्यावरण या पुरातात्विक रूप से संवेदनशील क्षेत्र नहीं हैं।

प्रस्तावित बुनियादी ढांचे के लिए ऐसे स्थान का चयन किया जिस से कम से कम प्रभाव हो। इनमें शामिल हैं (i) भूमि अधिग्रहण और लोगों के पुनर्वास की आवश्यकता से बचने के लिए सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर सुविधाओं का पता लगाना; और (ii) भूमि के अधिग्रहण को कम करने और विशेष रूप से शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में आजीविका पर प्रभाव को कम करने के लिए मुख्य/पहुंच सड़कों के साथ आरओडब्ल्यू में पाइप बिछाना

बेहतर बुनियादी ढांचे के स्थान, डिजाइन, निर्माण और संचालन के संबंध में संभावित प्रभावों की पहचान की गई। निर्माण चरण के दौरान, मुख्य रूप से अपशिष्ट मिट्टी की मध्यम मात्रा और निवासियों और यातायात की गड़बड़ी के निपटान की आवश्यकता से प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ये शहरी क्षेत्रों में निर्माण के सामान्य अस्थायी प्रभाव हैं, और उनके शमन के लिए अच्छी तरह से विकसित तरीके हैं। सभी नकारात्मक प्रभावों को स्वीकार्य स्तर तक कम करने के लिए शमन उपाय विकसित किए गए हैं। लाडनू सिटी उप-परियोजना के लिए अलग से पुनर्वास योजना (आरपी) तैयार की जाती है जो मुख्य रूप से शहर के प्रस्तावित क्षेत्रों में सीवर/पाइपलाइन बिछाने के परिणामस्वरूप आजीविका पर अस्थायी प्रभाव के मुद्दों को संबोधित करती है।

कार्यों का उचित समय निर्धारण (गैर-मानसून मौसम, कम यातायात घंटे, आदि) और सर्वोत्तम निर्माण विधियों द्वारा असुविधा को कम करने जैसे उपायों को नियोजित किया जाएगा जैसे कि 3.5 मीटर से अधिक की गहराई के लिए सीवर के लिए ट्रेचलेस पाइप बिछाने और उन क्षेत्रों में जहां यातायात है अधिक। व्यस्त सड़कों पर

पाइप/सीवर बिछाने के कार्य हेतु निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ठेकेदार द्वारा यातायात प्रबंधन योजना तैयार की जायेगी। परिचालन चरण में, सभी सुविधाएं और बुनियादी ढांचा नियमित रखरखाव के साथ संचालित होगा, जिससे पर्यावरण को प्रभावित नहीं होना चाहिए। समय-समय पर सुविधाओं की मरम्मत करने की आवश्यकता होगी, लेकिन निर्माण अवधि की तुलना में पर्यावरणीय प्रभाव बहुत कम होंगे और केवल छोटे क्षेत्रों को प्रभावित करेगा क्योंकि काम कम होगा।

पर्यावरण प्रबंधन- उपयुक्त एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपने के साथ-साथ स्वीकार्य स्तर तक सभी नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए शमन उपाय प्रदान करने के लिए एक पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) विकसित की गई है। विभिन्न डिजाइन संबंधी उपाय पहले से ही परियोजना डिजाइन में शामिल हैं। निर्माण के दौरान, ईएमपी में शमन उपाय शामिल हैं जैसे (i) जनता की असुविधा को कम करने के लिए सीवर कार्यों की उचित योजना बनाना; (ii) बैरिकेडिंग, धूल दमन और नियंत्रण के उपाय; (iii) सड़कों के किनारे और ढोने की गतिविधियों के लिए यातायात प्रबंधन के उपाय; (iv) पहुंच सुनिश्चित करने के लिए खाइयों के ऊपर पैदल मार्ग और तख्तों का प्रावधान बाधित नहीं होगा; और (v) निपटान मात्रा को कम करने के लिए उल्खनित सामग्रियों का यथासंभव लाभकारी उपयोग करना। ईएमपी उप-परियोजना के पर्यावरण के अनुकूल निर्माण का मार्गदर्शन करेगा। ईएमपी में ईएमपी कार्यान्वयन की प्रभावशीलता को मापने के लिए एक निगरानी कार्यक्रम शामिल है और इसमें ऑन- और ऑफ-साइट अवलोकन, दस्तावेज जांच और श्रमिकों और लाभार्थियों के साक्षात्कार शामिल हैं। अद्यतन ईएमपी/एसईएमपी की एक प्रति निर्माण अवधि के दौरान हर समय साइट पर रखी जाएगी। ईएमपी साइट पर काम करने वाले सभी ठेकेदारों के लिए बाध्यकारी होगा और इसे संविदात्मक खंडों में शामिल किया जाएगा। इस दस्तावेज में निर्धारित शर्तों के साथ गैर-अनुपालन, या कोई विचलन, अनुपालन में विफलता का गठन करेगा। संचालन चरण के प्रदर्शन की निगरानी के लिए, एसटीपी (कच्चे और उपचारित सीवेज गुणवत्ता), एसटीपी पर कीचड़ की उपचार दक्षता की निगरानी के लिए दीर्घकालिक सर्वेक्षण भी होंगे। इस तरह की कार्यवाहियों के लिए जिम्मेदार परियोजना एजेंसी के साथ शमन और निगरानी के उपाय, पर्यावरण प्रबंधन योजना का हिस्सा हैं। ईएमपी की अनुमानित कार्यान्वयन लागत 4,58,15,921/- (रुपये चार करोड़ अड़तालीस लाख पंद्रह हजार नौ सौ इक्कीस) रुपये है।

इस दस्तावेज में निर्धारित शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मसौदा आईईई और ईएमपी बोली और अनुबंध दस्तावेजों में था। ठेकेदार ने समीक्षा और अनुमोदन के लिए पीआईयू को एक अद्यतन ईएमपी / साइट-विशिष्ट ईएमपी (एसईएमपी) प्रस्तुत किया है जिसमें (i) निर्माण कार्य शिविरों के लिए प्रस्तावित स्थल / स्थान, भंडारण क्षेत्र, सड़कों, बिछाने के क्षेत्र, ठोस के लिए निपटान क्षेत्र शामिल हैं। और खतरनाक अपशिष्ट; (ii) अनुमोदित ईएमपी के बाद विशिष्ट शमन उपाय; और (iii) प्रति ईएमपी निगरानी कार्यक्रम। एसईएमपी की मंजूरी से पहले किसी भी कार्य को शुरू करने की अनुमति नहीं है। निर्माण अवधि के दौरान हर समय ईएमपी/अनुमोदित एसईएमपी की एक प्रति साइट पर रखी गई है।

कार्यान्वयन व्यवस्था- राजस्थान सरकार का स्थानीय स्वशासन विभाग (LSGD) RUDSICO के माध्यम से कार्य कर रहा है, जो परियोजना निष्पादन एजेंसी है। पीएमयू को बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के लिए रुडसिको के डिवीजन में रखा गया है। जयपुर और जोधपुर में दो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, और प्रत्येक परियोजना शहर/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) में पीआईयू हैं। पीएमयू एडीबी को पर्यावरण मूल्यांकन और निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करने, सुरक्षा उपायों के अनुपालन की निगरानी, सुरक्षा उपायों के मुद्दों को संबोधित करने, पीआईयू को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। पीआईयू ईएमपी कार्यान्वयन, सूचना प्रकटीकरण, परामर्श और अन्य क्षेत्र-स्तरीय गतिविधियों की दिन-प्रतिदिन की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। पीएमयू ने पर्यावरण के लिए एक परियोजना अधिकारी नियुक्त किया है और प्रत्येक पीआईयू ने एक सुरक्षा और सुरक्षा अधिकारी (एसएसओ) की प्रतिनियुक्ति की है। पीएमयू पर्यावरण परियोजना अधिकारी को

परियोजना प्रबंधन और क्षमता निर्माण सलाहकार (पीएमसीबीसी) और निर्माण प्रबंधन और पर्यवेक्षण सलाहकार (सीएमएससी) के विशेषज्ञों द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।

परामर्श, प्रकटीकरण और शिकायत निवारण। हितधारकों को साइट पर चर्चा और शहर स्तर पर एक सार्वजनिक परामर्श कार्यशाला के माध्यम से आईईई विकसित करने में शामिल किया गया था, जिसके बाद व्यक्त किए गए विचारों को आईईई और परियोजना की योजना और विकास में शामिल किया गया था। साइट पर सार्वजनिक परामर्श के अलावा, शहर स्तरीय समिति (सीएलसी) की एक हितधारक बैठक आयोजित की गई और सीएलसी ने उप-परियोजना की सराहना की और उसे मंजूरी दी। IEE को सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध कराया जाएगा, IEE के मसौदे (Draft) और पहले अद्यतन (first updated) किए गए IEE का खुलासा किया गया था, और इस अद्यतन IEE (updated IEE) को ADB और RUDSICO वेबसाइटों के माध्यम से व्यापक दर्शकों के लिए भी प्रकट किया जाएगा। परियोजना कार्यान्वयन के दौरान परामर्श प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा और विस्तारित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हितधारक परियोजना में पूरी तरह से लगे हुए हैं और इसके विकास और कार्यान्वयन में भाग लेने का अवसर है। आईईई के भीतर एक शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) का वर्णन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी सार्वजनिक शिकायत का त्वरित समाधान किया जा सके।

निगरानी और रिपोर्टिंग- निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए पीएमयू, पीआईयू और सलाहकार जिम्मेदार होंगे। निर्माण के दौरान, डीबीओ ठेकेदार द्वारा आंतरिक निगरानी के परिणाम पीआईयू को उनकी मासिक ईएमपी कार्यान्वयन रिपोर्ट में दिखाई देंगे। सीएमएससी की सहायता से पीआईयू, ठेकेदार के अनुपालन की निगरानी करेगा, एक त्रैमासिक पर्यावरण निगरानी रिपोर्ट (क्यूईएमआर) तैयार करेगा और पीएमयू को प्रस्तुत करेगा। पीएमयू कार्यान्वयन और अनुपालन की देखरेख करेगा और एडीबी को अर्ध-वार्षिक पर्यावरण निगरानी रिपोर्ट (एसईएमआर) प्रस्तुत करेगा। एडीबी पर्यावरण निगरानी रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर डालेगा। निगरानी रिपोर्ट को रुडसिको-ईएपी/पीएमयू वेबसाइट पर भी पोस्ट किया जाएगा।

निष्कर्ष और सिफारिशें - लाडनू शहर के नागरिक इस उप-परियोजना के प्रमुख लाभार्थी होंगे। बेहतर सीवरेज सिस्टम से मानव अपशिष्ट को उनके घरों से सुरक्षित और जल्दी से हटा दिया जाएगा। यह उप-परियोजना, बेहतर पर्यावरणीय परिस्थितियों के अलावा, शहर की समग्र स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करेगी। लोग स्वास्थ्य देखभाल पर कम खर्च करेंगे और बीमारी के कारण कम कार्यदिवस गंवाएंगे, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होना चाहिए, साथ ही साथ उनके समग्र स्वास्थ्य में भी सुधार होना चाहिए।

इसलिए उप-परियोजना से महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। डिजाइन, निर्माण और संचालन से जुड़े संभावित प्रभावों को उचित इंजीनियरिंग डिजाइन और अनुशंसित शमन उपायों और प्रक्रियाओं के समावेश या आवेदन के माध्यम से बिना कठिनाई के मानक स्तर तक कम किया जा सकता है। दूसरे अद्यतन आईईई के निष्कर्षों के आधार पर, कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है और परियोजना का वर्गीकरण "बी" श्रेणी के रूप में जारी है। उपपरियोजना भारत सरकार की ईआईए अधिसूचना (2006) के अंतर्गत नहीं आती है।

सिफारिशें- प्रारूप आईईई के निष्कर्षों के आधार पर इस उप-परियोजना के लिए लागू सिफारिश, इस अद्यतन के अनुसार आईईई के मसौदे की सिफारिशों की अनुपालन स्थिति इस प्रकार है;

इस अद्यतन के साथ पहले से लागू अनुशंसाएँ:

- (i) जल्द से जल्द सभी वैधानिक मंजूरी प्राप्त करें और सुनिश्चित करें कि शर्तों/प्रावधानों को विस्तृत डिजाइन में शामिल किया गया है;
- (ii) इस आईईई को बोली और अनुबंध दस्तावेजों में शामिल करें;

- (iii) सुनिश्चित करें कि परियोजना स्थलों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2000 और इसके संशोधन के अनुसार निर्दिष्ट निपटान स्थलों में निपटाए गए ठोस अपशिष्ट और अन्य उपद्रव सामग्री से हटा दिया गया है;
- (iv) सुनिश्चित करें कि फिकल स्लज (Faecal Sludge) प्रबंधन प्रोटोकॉल पर्यावरण नियमों (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2000 और इसके संशोधन) के अनुरूप हैं और ठोस अपशिष्ट निपटान में एक निर्दिष्ट साइट होनी चाहिए (खाली लॉट पर डंपिंग की अनुमति नहीं है);
- (v) साइट-विशिष्ट स्थितियों के अनुसार अभ्रक प्रबंधन योजना को अद्यतन करें;
- (vi) विस्तृत डिजाइन के आधार पर इस आईईई को अद्यतन/संशोधित करें और/या यदि अप्रत्याशित प्रभाव हों, कार्यक्षेत्र, संरक्षण, या स्थान में परिवर्तन;
- (vii) अनुबंध प्रदान करने पर ठेकेदार के लिए रक्षोपाय इंडक्शन करना;
- (viii) ईएमपी कार्यान्वयन का कड़ाई से पर्यवेक्षण करें;
- (ix) सुनिश्चित करें कि ठेकेदार ने काम शुरू करने से पहले योग्य ईएचएस अधिकारियों को नियुक्त किया है;
- (x) आईईई में बताए अनुसार नियमित आधार पर दस्तावेजीकरण और रिपोर्टिंग;
- (xi) हितधारकों के साथ निरंतर परामर्श;
- (xii) सूचना का समय पर प्रकटीकरण और शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) की स्थापना;
- (xiii) प्रथम स्तर के जीआरएम में उपठेकेदारों सहित ठेकेदारों की भागीदारी;
- (xiv) परियोजना कार्यान्वयन के दौरान पर्यावरण और लोगों को किसी भी प्रभाव से बचाने के लिए पीएमयू, पीआईयू, परियोजना सलाहकारों और ठेकेदारों की प्रतिबद्धता।